

# ପ୍ରସାଦ

वर्ष : 08 अंक : 301

प्रयागराज, मंगलवार 14 फरवरी, 2023

# हिन्दी दैनिक

ਪ੍ਰਾਚ—4

मूल्य : 3 रुपया

अडानी मुद्दे पर हंगामे के बीच राज्यसभा 13 मार्च तक स्थगित, लोकसभा में कार्यवाही जारी



पाठों ताहता जायकर विद्या पढ़ा पर  
सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के  
कारण राज्य सभा की कार्यवाही 20  
मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।  
पूर्वाह्न सदन की कार्यवाही शुरू करते  
हुए श्री धनखड़ ने कहा कि आज दो  
सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस  
दिया है जिसमें एक नोटिस आम आदमी  
पार्टी के संजय सिंह का और दूसरा  
संतोष कुमार पी का है। उन्होंने गहरी  
नाराजगी जताते हुये कहा कि श्री संजय  
सिंह सिर्फ तारीख बदलकर एक ही

बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि एक ही मुद्दे पर बार-बार नोटिस देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो दो नोटिस मिले हैं वे प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं।

शून्यकाल शुरू करते हुये उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे लेकिन हँगामे का हवाला देकर वे नहीं बोले। सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने हालांकि अपने मुद्दे

नेता मलिकार्जुन खड्गे ने कुछ बोलना चाहा तो श्री धनखड ने कहा कि जिन शब्दों को कार्यावाही से हटाया गया है उसी का उल्लेख किया जाना उचित नहीं है। कांग्रेस सदस्यों के बार-बार कहने पर सभापति ने श्री खड्गे को अपनी बात रखने के लिए कहा। इस पर श्री खड्गे फिर से उन्हें शब्दों को लेकर बोलने लगे। उन्होंने श्रीमती पाटिल को निलंबित किये जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने

# जनजातीय समूहों का विकास का सर्वाधिक जरूरत : मुर्मू



काया को प्रशंसा करत हुय उन्होने कहा कि राज्यपाल ने गाँवों को गोद लेने का कार्यक्रम चलाकर इस क्षेत्र में विकास के लिए बड़ा कार्य किया है। उन्होने कहा कि मुसहर जनजाति के लोग जंगलों में रहते हैं। उनकी खुद की जमीन न होने से वे प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं जुड़ पाते। उन्होंने समाज के लोगों का नसीहत दी कि सीखना बहुत जरूरी है। बेटा हो या बेटी, दोनों को पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा "जिंदगी जीने के लिए घर जरूरी है।

# डिजिटल इकॉनमी : सीएम योगी



सीएम योगी ने कहा कि तकनीक का लाभ किस रूप में प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो रहा है यह देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना के वितरण वें रूप में देखी जा सकती है। यूपी में 80 हजार फेयर प्राइज शॉप्स हैं। छह साल पहले एक शिकायत होती थी कि खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिल पाता है। हमने जब ई पॉज मशीन लगाई तो प्रदेश के अंदर हमने उनकी मॉनीटरिंग प्रारंभ की। आज परिणाम है कि 15 करोड़ लोगों को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से हम खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं और तकनीक वें माध्यम से 1200 करोड़ रुपए

कहा कि 'सरकार के दबाव में' ऐसा किया गया है। इसी बीच सभापति ने उन्हें रोकते हुये कहा कि आप बार-बार सदन में और सदन के बाहर यही कहते हैं। उन्होंने कहा, "मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं नियम के अनुसार और संविधान तथा देशवासियों के हित में काम करता हूँ।" उन्होंने कहा कि 'सरकार के दबाव में' शब्द को कार्यवाही से हटाया जा रहा है।

इसके बाद उन्होंने सत्तापक्ष के

इसके बाद उन्हान सत्तापक्ष के सदस्यों को शून्यकाल पर बोलने के लिए पुकारा तभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी सदस्य सदन के बीचोबीच आकर नारेबाजी करने लगे। सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस पर कहा कि इस तरह का व्यवहार कब तक चलेगा। हंगामा करने वाले सदस्यों का नाम लिया जाना चाहिए और सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थिरित कर सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा की जानी चाहिए। इस पर सभापति ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राधव चद्दडा, संजय सिंह, कांग्रेस की रंजीत रंजन, शक्ति सिंह गोहिल, इमरान प्रतापगढ़ी आदि का नाम पुकारा। स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर सभापति ने शून्यकाल शुरू करने की कोशिश की।

के पास यह आधिकार है कि वह इकासी भी सदस्य का निलंबन वापस ले सकते हैं और जेपीसी की मांग को पूरा कर सकते हैं। इस पर सदन के नेता श्री गोयल ने कहा कि निलंबन वापस लेने की जिम्मेदारी सभापति पर नहीं डाली जानी चाहिए। यह काम विपक्षी सदस्य भी अपने आचरण को सुधार कर और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुयी चर्चा का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तर दिये जाने के दौरान करीब सवा घंटे तक किये गये अपने व्यवहार के लिए माफी मांग कर पूरा कर सकते हैं। इससे पहले श्री एनखड़ ने कहा कि वह सिर्फ संविधान और उसकी मूल भावना के अनुरूप ही सदन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का रुख बजट सत्र के शुभारंभ से ही नकारात्मक रहा है। दो दल राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल

ऐसा ने आप के पारा, "मैं कर सार के कहा को के के दमी ददन उरने त ने बहार वाले हिए अमय के गानी कहा छढ़ा, जन, मगढ़ी बाद ने ने शेश

इसी दौरान कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि सदन को संविधान के अनुरूप ही चलाया जाना चाहिए और हिंडूनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जेपीसी से जांच करायी जानी चाहिए। तभी श्री एनखड़ ने कहा कि जिस विषय पर सदन में एक बार व्यवस्था दी जा चुकी है और उसी को बार-बार उठाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी बीच कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का सवाल उठाते हुये कहा कि सभापति के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य का निलंबन वापस ले सकते हैं और जेपीसी की मांग को पूरा कर सकते हैं। इस पर सदन के नेता श्री गोयल ने कहा कि निलंबन वापस लेने की जिम्मेदारी सभापति पर नहीं डाली जानी चाहिए। यह काम विपक्षी सदस्य भी अपने आचरण को सुधार कर और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रत्यावर पर हुयी चर्चा का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तर दिये जाने के दौरान करीब सवा घंटे तक किये गये अपने व्यवहार के लिए माफी मांग कर पूरा कर सकते हैं। इससे पहले श्री एनखड़ ने कहा कि वह सिर्फ संविधान और उसकी मूल भावना के अनुरूप ही सदन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का रुख बजट सत्र के शुभारंभ से ही नकारात्मक रहा है। दो दल राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल



उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार सर्वर बंद कर देती है जिससे युवाओं को नुकसान होता है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस मुद्रा को लेकर राजस्थान सरकार से वापस प्राप्तीकरण मार्गे। भाजपा के ही रामबांदी बोहरा ने शून्यकाल में राजस्थान राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पत्रकारों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री अखबारों पर दबाव बना रहे हैं कि विज्ञापन उन्हें दिए जाएंगे जो उनकी खबर छाप रही है। उनका कहना था कि इस तरह राजस्थान मामलों के लिए एक समिति भी गठित की गई जिसने इन खबरों की पुष्टि की है। उन्होंने केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से इस मामले वाले संज्ञान में लेने का आग्रह किया।

## पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए रोजगार पोर्टल बनाने की मांग

२८

A photograph showing a large group of people, predominantly men, seated in rows of red plastic chairs. They are all dressed in white shirts and ties, suggesting a formal or organized event. Many individuals are clapping their hands. In the background, there's a building with a prominent blue and white striped awning. The overall atmosphere appears to be a public gathering or a formal meeting.

# भारत ने 8-9 दिन में रक्षा उत्पादन क्षत्र का किया कायाकल्प : मोदी



मानों के स्थिलाफ हिंसा रोकने के लिए समग्र विधेयक लाए सरकार : थलर

पांच वर्ष में दश का रक्षा नियात छह गुना बढ़ा है और उसने अपने नियर्त में 1.5 अरब डॉलर के आंकड़े को हमने पार कर लिया है। पांच दिवसीय प्रदर्शनी को एशिया में सबसे बड़ी प्रदर्शनी माना जाता है। इसमें 700 से अधिक भारतीय और विदेशी रक्षा कंपनियां और 100 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें कई देशों के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। मोदी ने कहा, 'आप भी जानते हैं कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी प्रौद्योगिकी को, जिसके बाजार को और जिसके व्यापार को सबसे जटिल माना जाता है। इसके बावजूद, भारत न बात 8-9 साल के भीतर-भीतर अपने यहां रक्षा क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए, हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम नियर्त के इस आंकड़े को डेढ़ अरब डालर से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। मोदी ने कहा कि रक्षा एवं एयरोस्पेस के क्षेत्र में किए गए प्रयास भारत के लिए एक 'लांच पैड' की तरह काम करेंगे। अटिकारियों ने कहा कि 'एरो इंडियाइश' में लगभग 250 कंपनी से कंपनी समझौते (बी2बी) होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 75,000 कराड़ रुपय का निवेश मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में आयोजित एक एयर शो में भारतीय वायुसेना के कई विमानों ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। 'एरो इंडिया' का विषय 'द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटीज' है और इसका उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में भारत की प्रगति और क्षमताओं को पेश करना है। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'एरो इंडियाइश' भारत में एरोस्पेस क्षेत्र के आगे विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

**दिल्ली।** कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोमवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि स्थायकमंत्रियों के खिलाफ होने वाली हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए एक समय विधेयक लाया जाना

स्वास्थ्यकानियों के खिलाफ हानि वाला हस्ता का घटनाओं का राक्षण के लिए एक समग्र विधेयक लाया जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मांग की। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरुर ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले बढ़े हैं। स्वास्थ्यकर्मी देश के नागरिकों की सेवा कर रहे हैं और जिंदगियां बचा रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार इससे जुड़ा एक विधेयक लेकर आई थी, लेकिन कोई कारण बताए बिना इसे वापस ले लिया गया। उन्होंने आग्रह किया, ‘‘स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए एक समग्र विधेयक लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के कुछ नेताओं की कथित हत्या का विषय उठाया। उन्होंने दावा किया, ‘‘पिछले एक महीने में भाजपा के चार पदाधिकारियों की हत्या की गई है। यह राजनीतिक घटनात्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल रही है। हमारे लोगों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। साव ने आग्रह किया, ‘‘स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। केंद्र सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करे। भाजपा के निशिकांत दुबे ने झारखण्ड के संथाल परगना इलाके में जनसंख्या असंतुलन का विषय उठाया और एनआरसी लागू करने की मांग की। उन्होंने दावा किया, ‘‘बांगलादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। यहां आदिवासी संस्कृति पर असर पड़ रहा है। दुबे ने कहा, ‘‘संथाल के छ जिलों में एनआरसी लागू किया जाए।



**नई दिल्ली।** कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में चल रहे अतिक्रमों के खिलाफ आज भवा का बुलाया। इसके दौरान वाड़ा ने उल्लंघनों पर धमकी दी।

विरोधी अभियान को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शांति और विश्वास के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है न कि "बुलडोजर के नीचे उनके अधिकारों को कुचलना"। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस अभियान के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है और इसे तत्काल समाप्त करने की मांग की है। राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव विजय कुमार विधूड़ी के सभी उपायुक्तों को सात जनवरी से जम्मू-कश्मीर में सरकारी जमीन से 100 प्रतिशत अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करने के निर्देश के बाद अब तक जम्मू-कश्मीर में 10 लाख कनाल (एक कनाल= 605 वर्ग गज) से अधिक भूमि को पुनः कब्जे में लिया जा चुका है। हिंदी में किए गए एक ट्वीट में प्रियंका ने आरोप लगाया कि लदाख में अपने संवैधानिक अधिकारों की बहाली रही है। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया, कश्मीर में आम जनों की सुनवाई किए बिना उनके घरों पर लोगों से बनता है। शांति व भरोसे के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, न कि उनके अधिकारों





